देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vps/06 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 12 सितम्बर 2020

भाग-1

आखिर क्यूँ नहीं हो रहे क्रेन सर्विस के टेंडर?

जयपुर आयुक्तालय क्षेत्र मे नो पार्किंग ज़ोन में खड़े होने वाले चौपहिया वाहनों को उठाने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने दो बार निकाली 1.5 करोड़ की निविदा

जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा जयपुर शहर में नो पार्किंग ज़ोन में खड़े होने वाले चौपहिया वाहनों को उठाने के लिए महज दो महीने में दो बार 1.5 करोड़ रूपये की निविदा निकाली गयी,निविदा की शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को 1.5 टन वजन उठाने की क्षमता वाली 12 पिक एंड केरी क्रेनों की सुविधा पुलिस आयुक्तालय को उपलब्ध करवानी थी|शर्तों के अनुसार खुद के स्वामित्व की 5 क्रेनों वाला बोलीदाता ही निविदा में भाग ले सकता था|अनुबंधकर्ता को एक क्रेन पर 12 घंटों के लिए एक चालक, खलासी और 4 हेल्परो की व्यवस्था करनी थी और उसे पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर के निर्देशानुसार ही निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना था|अनुबंधकर्ता को 2880 वाहन प्रति क्रेन प्रति वर्ष उठाने का लक्ष्य दिया गया था|यह क्रेने निम्न उपयोग में लानी थी:-

- वाहनों को नो पार्किंग क्षेत्र से उठाकर निर्धारित स्थान पर ले जाने हेतु|
- यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहनों को उठाकर निर्धारित स्थान पार ले जाने हेतु|
- दुर्घटना ग्रस्त वाहनों को उठाकर निर्धारित स्थान पर खड़े करने हेतु|
- एम.वी. एक्ट में जब्त वाहनों को निर्धारित स्थान पर छोड़ने हेतु|
- पुलिस उपायुक्त(यातायात) के निर्देशानुसार अन्य कार्य हेतु|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आखिर क्या वजह है जिसके कारण ठेकेदार नहीं दिखा रहे इस टेंडर में रूचि?

(1) सी.एम. के चहेते मंत्री का तुगलकी फरमान,नहीं उठने चाहिए मेरे एरिये से वाहन!

ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार में जयपुर के ही विधायक और बड़े विभाग के मंत्रीजी,जो कि अपने बडबोलेपन के लिए जाने जाते है और हाल ही में सचिन पायलट के विरुद्ध बयांन(चड्डी/निक्कर से जुड़ा जुमला) देने से सुर्ख़ियों में आये थे, के एक तुगलकी फरमान ने वाहन उठाने वाले अनुबंधकर्ता को आफत में डाल दिया है|मंत्रीजी के आदेश है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से किसी भी तरह के नियम तोड़ने वाले किसी भी उल्लंघनकर्ता का वाहन नहीं उठना चाहिए भले ही वाहन चालक ने वाहन नो पार्किंग में लगा रखा हो या मनमाने तरीके से सरकारी रास्ता अवरुद्ध कर रखा हो|मंत्रीजी ने अपने फरमान की अक्षरत: पालना के लिए बाकायदा एक नक्शा भी आयुक्तालय के जिम्मेदार अधिकारी महोदय के पास उपलब्ध करवा दिया है|यदि ऐसे ही फरमान शहर के बाकी विधायक भी देने लग गए तो वह दिन दूर नहीं जब शहर की कानून व्यवस्था ही चौपट हो जायेगी|

(2) कोरोना बना कारण

कोरोना के चलते पिछले 7 महीने से गाड़ियाँ उठाने का काम ठप्प पड़ा हुआ है|मुख्यालय द्वारा लिखित में आदेश जारी कर सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी उल्लंघनकर्ता का वाहन नहीं उठाने के लिखित आदेश जारी किये है|ऐसे में वाहन उठाने वाले अनुबंधकर्ता के सामने दोहरी मुसीबते आ खड़ी हुई है एक तो उसकी रोज की कमाई मारी गयी दूसरा उसे अपने आदमियों को महीने की तनख्वाह भी देनी पड़ रही है क्यूंकि पुलिस मुख्यालय से कभी भी काम वापस चालू करने का फरमान आ सकता है ऐसे में जल्दबाजी में आदमी मिलना भी मुश्किल हो जाता है|

(3) टेंडर की शर्ते बनी गलफांस

जयपुर शहर में इस व्यवस्था से जुड़े ठेकेदारों द्वारा बताया गया कि पिछले कई सालों से यह टेंडर परिवहन विभाग द्वारा ओपरेट किया जाता था जहाँ पर मंथली मोड़ पर पेमेंट रिलीज किया जाता था जो कि सुविधा का विषय थी क्यूंकि इस व्यवस्था में ठेकेदार को केवल निर्धारित पॉइंट्स पर क्रेने मय आदमी और डीजल पानी के उपलब्ध करवानी थी,गाड़ियाँ उठे चाहे नही उठे, उसे उसके निर्धारित क्रेनों का मासिक भुगतान मिल जाता था|परन्तु पिछले एक साल से यह टेंडर पुलिस आयुक्तालय द्वारा निकाला जा रहा है ,जिसमे प्रति क्रेन 2880 वाहन वार्षिक उठाने का लक्ष्य है|परन्तु यह टारगेट बमुश्किल ही पूरा हो पाता है क्यूंकि कई बार VIP मूवमेंट,ऊपरी दबाव के चलते गाड़ियाँ बिना चालान छोडनी पड़ती है|गाडी में बैठने वाला ट्रेफिक पुलिस का सिपाही इस टेंडर में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है वह अपने निजी हित और स्वार्थ सिद्धि के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से सांठ-गाँठ कर लेता है और ले-देकर बिना चालान बनाये गाडी को छोड़ देता है|इसके बदले वह क्रेन चालक,खलासी को रोज की बंधी दे देता है,शहर के चारो कोनो में चलने वाली 12 क्रेनों पर नजर रखना किसी भी ठेकेदार के लिए संभव नहीं है|इस प्रकार पुलिसकर्मी और क्रेन चालको की इस मिलीभगत से ठेकेदार के लक्ष्य पुरे नहीं हो पाते और उसे घाटा उठाना पड़ता है|

यातायात अवरुद्ध: निजी स्तर पर मंगवाकर ले रहे सहायता

यातायात पुलिस के पास क्रेन नहीं, नो पार्किंग से नहीं उठते वाहन

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. यातायात पुलिस बिना क्रेन के ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही है। लॉकडाउन और फिर अनलॉक के दौरान भले ही उन्हें क्रेन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन गत शुक्रवार को आई भारी बरसात के दौरान क्रेनों की कमी खली।

बरसात के कारण शहर की सड़कें दरिया बन चुकी थी। जगह-जगह चौपहिया वाहन पानी में अटक गए थे। यातायात पुलिस के कंट्रोल रूम पर मदद के लिए फोन भी बहुत आए, लेकिन मजबूर यातायात पुलिस कुछ खास कर नहीं सकी। निजी स्तर पर पुराने ठेकेदार की ही मदद लेकर यातायात की बाधा दूर करने में जुटी रही। दरअसल यातायात पुलिस को प्राप्त क्रेनों का ठेका पूरा हो गया था। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन तकनीकी खामी के कारण उसे फिर शुरू किया। अप्रेल से क्रेन नहीं है और अभी भी पता नहीं क्रेन कब मिलेगी।

नो पार्किंग से उठाए वाहन

6266	47	6313
जनवरी से मार्च	जून और जुलाई	कुल

यातायात पुलिस के पास अभी क्रेन नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में खामी आने के बाद पुन:शुरू की है। जल्द ही यातायात पुलिस को क्रेन मिल जाएगी।

राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय

10 क्रेन का हो रहा था उपयोग

इससे पहले शहर में यातायात पुलिस ठेके पर दस क्रेन का उपयोग कर रही थी। जिनसे न सिर्फ नो पार्किंग से वाहनों को हटाकर के चालान किए जा रहे थे, बल्कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और आमजन की मदद के लिए क्रेनों को भेजा जाता था। एमवी एक्ट के तहत वाहन उठाने का शुल्क लिया जाता था। लॉकडाउन के दौरान क्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अनलॉक होने और वाहनों की आवाजाही शुरू होने के बाद फिर से नो-पार्किंग की कार्रवाई जरूरी हो गई है।

सैकड़ों शिकायत मिली

एक सप्ताह शुक्रवार पहले आई भारी बरसात के दौरान यातायात पुलिस को सैकड़ों शिकायत विभिन्न इलाकों से मिली। स्वयं की क्रेन न होने के कारण पूर्व की ठेका फर्म से क्रेनों को भेजा गया। वाहन मालिकों ने ही वाहन उठाने का चार्ज दिया।

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 25/08/2020 को प्रकाशित खबर

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10/09/2020 को प्रकाशित खबर

हो गया। देर रात तक ट्रक को हटवाने की कवायद की जा रही थी।

10/09/RP

जल्द मिलेंगी 12 क्रेन, दूर होगा यातायात अवरुद्ध

खासा कोठी पर क्रेन हाउस बनाया

फॉलोअप

खासाकोठी पर क्रेन हाउस का उद्घाटन करते डीसीपी ट्रैफिक

जयपुर @ पत्रिका. शहर यातायात पुलिस के बेड़े में जल्द ही 12 नई क्रेन शामिल हो जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहीं, बुधवार को डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिधु ने खासाकोठी पर नए क्रेन हाउस का उद्घाटन किया। सिधु ने बताया कि सड़कों पर वाहन खड़ा करके यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे स्टेशन, सत्र न्यायालय, कलक्ट्रेट के आस-पास आमजन की सुविधा को देखते हुए खासकोठी पर क्रेन हाउस का संचालन किया जाएगा। गत अप्रैल माह में कम्पनी का ठेका समाप्त हो गया था। राजस्थान पत्रिका ने 'यातायात पुलिस के पास क्रेन नहीं, नो पार्किंग से नहीं उठते वाहन' समाचार प्रकाशित कर संसाधनों की कमी का खुलासा किया था। जिसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। अब जल्द ही 12 क्रेनों का यातायात पुलिस उपयोग कर सकेंगी।

किसी बोलीदाता के नहीं आने से रद्द हुई निविदा

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार जनवरी से जुलाई तक 6313 वाहन ही उठाये गए है|जबकि निविदा के अनुसार ठेकेदार को करीब पैंतीस हजार वाहन हर साल उठाने होते है तब जाकर उसका खर्चा निकलता है|परन्तु मंत्रीजी के फरमान ,कोरोना,टेंडर की शर्तों ने वाहन उठाने वाली निविदा पर संकट के बादल खड़े कर दिए और किसी बोलीदाता के नहीं आने से निविदा रद्द करनी पड़ी|

जिम्मेदार नहीं बता रहे असली कारण

पत्रिका में प्रकाशित खबर के अनुसार जयपुर कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय श्री राहुल प्रकाश के कथनानुसार टेंडर प्रक्रिया में खामी के कारण टेंडर प्रक्रिया निरस्त की गयी जो कि वास्तविकता से परे है|जयपुर में फिलहाल दो-तीन पार्टियाँ ही है जो इस टेंडर को लेने में सक्षम है|इन पार्टियों द्वारा इस टेंडर से हाथ खींच लेने से ही इस निविदा को दो बार निरस्त करना पड़ाजिसका मुख्य कारण उक्त तुगलकी फरमान भी है|गौरतलब है कि मई माह में इस निविदा को निकाला गया था,जिसमे किसी के नहीं आने पर जून में इसी टेंडर को दुबारा प्रकाशित किया गया इस तरह दो माह में ही दो बार टेंडर करने के बावजूद जयपुर शहर को क्रेन सर्विस नहीं मिल पा रही है|

यातायातकर्मियों की ऊपरी कमाई में आई बेतहाशा कमी,करवा रहे दूसरी जगह बदली

गाड़ियाँ नहीं उठने से ना केवल ठेकेदार परेशान है बल्कि इस कार्यवाही में तैनात पुलिसकर्मी भी एक तरीके से केवल तनख्वाह पर गुजारा करने पर मजबूर है|इन मुसीबतों से उनकी उपरी कमाई में बेतहाशा कमी आई है|इसके चलते कई यातायातकर्मी और अधिकारीगण तो अपनी बदली करवाने तक की सिफारिशे लगवाने में लगे हुए है|कई कामयाब भी हो गए है,कई अभी भी सिटी बजाते/गाड़ियाँ रोकते नजर आ जाते है|

क्या हो रास्ता?

वाहनों के नहीं उठने से जहाँ पर ठेकेदार को नुकसान और सरकार को राजस्व के करोडो रुपयों की हानि हो रही है यदि जयपुर कमिश्नरेट के जिम्मेदार अधिकारी वाकई जयपुर शहर में ट्रेफिक व्यवस्था को सुचारू करना चाहते है तो उन्हें निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा:-

- परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में निकाले जा रहे टेंडरों का अध्ययन करना होगा और समुचित एवं यथासंभव संशोधन भी करना होगा|
- RTTP ACT 2012 की शर्तों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में प्री-बिड मीटिंग की व्यवस्था करनी होगी|प्री बिड मीटिंग में आये सुझावों का अध्ययन कर ,सही सुझावों को मानते हुए,उन्हें अमलीजामा पहनना होगा|
- 2880 प्रति वाहन प्रति वर्ष का लक्ष्य ठेकेदार को ना देकर सम्बंधित ट्रेफिक के सिपाहियों,सब इंस्पेक्टरों,इंस्पेक्टरों के तय किये जाने होंगे अन्यथा ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी राजस्व को हानि पहुचाते रहेंगे|
- पुलिस को राजनैतिक दबाव से मुक्त करना होगा और मंत्रियों,संतरियों ,VIP लोगो की सिफारिशे नही मानकर समान न्याय की भावना से काम करना होगा|